

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] No. 268] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASHADHA 7, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 22 जून, 2016

सं.टीएएमपी/11/2013-सीएचपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा,चेन्नई पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता, एतद्द्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2013-सीएचपीटी

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2016 के 21वें दिन पारित)

यह आदेश चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के वर्तमान दरमानों की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंधित है।

2. चेन्नईपत्तन न्यास (सीएचपीटी) के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं.टीएएमपी/11/2013-सीएचपीटी दिनांक 04 अगस्त, 2014 के अंतर्गत अनुमोदित और भारत के राजपत्र में 17 सितंबर, 2014 को अधिसूचित किये गये थे जिसमें दरमानों की वैधता 31 मार्च 2016 तक निर्धारित थी।

3226 GI/2016 (1)

- 3. चेन्नई पत्तन न्यास के दिसंबर 2015 के अनुरोध पत्र के आधार पर चेन्नई पत्तन न्यास के दरमानों की वैधता, प्राधिकरण के आदेश सं टीएएमपी/11/2013-सीएचपीटी दिनांक 30 मार्च 2016 के द्वारा 30 जून 2016 तक बढ़ा दी गई थी जिसे भारत सरकार के राजपत्र में राजपत्र सं 150 पर, 25 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किया गया था।
- 4. चेन्नई पत्तन न्यास ने अपने पत्र सं. ए.ओ.(एसओआर)/10611/2015/एफआर दिनांक 04 अप्रैल 2016 के अंतर्गत, कार्यात्मक दिशानिर्देश-2015 तथा प्रशुल्क नीति का अनुसरण करते हुए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर नई प्रशुल्क नीति और कार्यात्मक दिशानिर्देश, 2015 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
- 5. पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा तत्कालीन पोत परिवहन तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनवरी 2005 में जारी तटीय रियायत नीति में आंशिक संशोधन करते हुए,17 सितंबर, 2015 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को निदेश जारी किए गए थे। पोत परिवहन मंत्रालय के 17 सितंबर, 2015 के पत्र के अनुसार तटीय पोतों व तटीय कंटेनरों के लिए पोत एवं कंटेनर संबंधी प्रभारों में अमेरिकी डॉलर बनाम भारतीय रुपया के मूल्यों की गणना में विनिमय दर के उतारचढ़ाव को स्थान दिया जाए ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधी प्रभार तथा सभी तटीय कंटेनरों के लिए कंटेनर संबंधी प्रभार उसके संगत प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। पोत परिवहन मंत्रालय के ये निदेश प्राधिकरण के दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 के आदेश द्वारा संप्रेषित कर दिए गए थे। परंतु, इसके पश्चात पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा,11 मई 2016 के पत्र के माध्यम से इससे पहले 17 सितंबर, 2015 को जारी आदेश को स्थिगत करने के निदेश दिए गए हैं। इसलिए प्राधिकरण द्वारा जारी 05 अक्तूबर, 2015 के आदेश को स्थिगत करने के लिए भी, 19 मई, 2016 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- 6.1. चेन्नई पत्तन न्यास ने 25 मई, 2016 के ईमेल के अंतर्गत इस संबंध में उल्लेख किया है कि अप्रैल, 2016 में, सामान्य आशोधनों के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय तटीय पोतों से आय का आकलन, प्राधिकरण द्वारा जारी 05 अक्तूबर, 2015 के आदेश के आधार पर किया गया है तथा 04 अप्रैल, 2016 को प्रस्तुत उनके सामान्य आशोधन प्रस्ताव में, प्राधिकरण के अस्थायी-स्थगन आदेश दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 के आधार पर आशोधन के लिए प्राधिकरण के अगले आदेश के जारी होने तक, प्रतीक्षा करने या न करने की पृष्टि करने का अनुरोध किया है।
- 6.2 इस संदर्भ में प्राधिकरण ने 25 मई, 2016 के पत्र के माध्यम से चेन्नई महापत्तन न्यास को,अपने प्रस्ताव की, प्राधिकरण के 19 मई, 2016 के आदेश के आधार पर पुनरीक्षा करने तथा प्रशुल्क नीति-2015 व कार्यात्मक दिशार्निर्देश के अनुसरण में आशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया है।

7.1. चेन्नई महापत्तन न्यास द्वारा 15 जून 2016 के प्रस्ताव के अंतर्गत निम्न उल्लेख किए गए हैं

- (i). दरमानों में सामान्य आशोधन के लिए दिनांक 04 अप्रैल, 2016 का प्रस्ताव, चेन्नई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड की 27 मई, 2016 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ने बीआर सं 29 दिनांक 27 मई, 2016 के अंतर्गत, प्राधिकरण को 04 अप्रैल, 2016 को प्रेषित प्रस्ताव की औपचारिक तौर पर पृष्टि कर दी है तथा प्रस्ताव को प्राधिकरण के आदेशों/उपयोक्ता की टिप्पणियों के आधार पर आशोधित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- (ii). प्रस्ताव को, प्राधिकरण के आदेश और बोर्ड के निदेशों के अनुसार आशोधित करने संबंधीकार्रवाई की जा रही है। तटीय पोतों के लिए पोत संबंधी प्रभार, पहले की भांति पुन: लगाने से राजस्व में कमी होगी, तथा उपयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों पर भी विचार करते हुए प्रस्ताव की पुनरीक्षा की जा रही है तथा आशोधित प्रस्ताव 30.6.2016 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
- (iii). इसके अतिरिक्त,क्योंकि मौजूदा दरमानों की वैधता की अवधि 30 जून, 2016 को समाप्त हो रही है, इसलिए प्राधिकरण से अनुरोध है कि मौजूदा दरमानों की वैधता की अवधि 30-9-2016 या आशोधित दरमान लागू होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

8. चेन्नई पत्तन न्यास के उपर्युक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में कि चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव की जांच पड़ताल करनी होगी तथा चेन्नई पत्तन न्यास से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात इस पर कार्रवाई के लिए कुछ समय अपेक्षित है और यह कि चेन्नई पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता 30.06.2016 तक है, इस प्राधिकरण द्वारा, चेन्नई पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता अविध में, 30.6.2016 से आगे तीन माह के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2016 तक या संशोधित दरमान प्रभावी होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया जाता है। चेन्नई पत्तन न्यास को परामर्श दिया जाता है कि वह अपना प्रस्ताव, यथा सहमति, 30 जून, 2016 से पूर्व, हर हालत में प्रस्तुत कर दे।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त) [विज्ञापन—III/4/असा./143/16**(**152**)**]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd June, 2016

No. TAMP/11/2013-CHPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/11/2013-CHPT

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st day of June 2016)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).

- 2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/11/2013-CHPT dated 4 August 2014 which was notified in the Gazette of India on 17 September 2014. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2016.
- 3. Based on the request made by CHPT vide its letter of December 2015, this Authority had extended the validity of SOR of CHPT upto 30 June 2016 vide Order No. TAMP/11/2013-CHPT Dated 30 March 2016 which was notified in the Gazette of India on 25 April 2016 vide Gazette No. 150.
- 4. The CHPT has filed its proposal following the Tariff Policy and working guidelines 2015, vide its letter No. A.O. (SOR)/10611/2015/FR dated 4 April 2016 and it is under process as per the usual consultation procedure following the new Tariff Policy and Working Guidelines, 2015
- 5. The MOS vide its letter dated 17 September 2015 had issued a direction to this Authority partially modifying the coastal concession policy issued by the (then) MSRTH in January 2005. As per the letter dated 17 September 2015 of the MOS, vessel related charges and container related charges for coastal vessels and coastal containers should take into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee vis-à-vis the US \$ so that vessel related charges for all coastal vessels and the container related charges for all coastal containers should not exceed 60% of the corresponding charges. This direction of the MOS was communicated by this Authority by passing an Order dated 5 October 2015. However, the MOS vide its subsequent letter dated 11 May 2016 has directed to keep its earlier direction dated 17 September 2015 in abeyance. Therefore, this Authority has passed an Order dated 19 May 2016 to keep its Order dated 5 October 2015 also in abeyance.
- 6.1. In this connection, the CHPT vide its e-mail dated 24 May 2016 has stated that while submitting its general revision proposal in April 2016, the income estimation from coastal vessels has been calculated based on the Order dated 5 October 2015 passed by this Authority and requested us to confirm whether the general revision proposal submitted by

it on 04 April 2016 needs to be modified, based on the temporary abeyance Order of this Authority dated 5 October 2015 or whether to wait for further orders from this Authority.

- 6.2. In this context, we have vide our letter dated 25 May 2016 advised the CHPT to review its proposal based on the Order dated 19 May 2016 of this Authority and file its revised proposal immediately following the Tariff Policy, 2015 and Working Guidelines.
- 7.1. Now, the CHPT vide its letter dated 15 June 2016 has made the following submissions:
 - (i) The proposal dated 4.4.2016 for General revision of Scale of Rates has been placed before the Board Trustees of Chennai Port Trust in the meeting held on 27.5.2016. The Board vide B.R.No.29 dated 27.5.2016 has ratified the proposal sent to TAMP on 4.4.16 and also approved to modify the proposal based on TAMP orders / users comments.
 - (ii) Action is being taken to revise the proposal as per TAMP order and Board directions. Considering that there will be revenue reduction on account of restoring old practice of levy of vessel related charges for coastal vessels and also taking into consideration comments received from the users, the proposal is being reviewed and the revised proposal will be submitted on or before 30.6.2016.
 - (iii) Further, since the validity of the existing Scale of Rates is expiring on 30.6.2016, TAMP is requested to extend the validity of the existing Scale of Rates upto 30.9.2016 or till the implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.
- 8. In view of the above submissions made by the CHPT and considering that the revised proposal to be filed by CHPT may have to be scrutinized and it would take some more time after the receipt of proposal from the CHPT, for the case to mature for final disposal and recognizing that the extended validity of the existing SOR of CHPT expires on 30 June 2016, this Authority extends the validity of the existing SOR of CHPT beyond 30 June 2016 for another period of three months i.e. up to 30 September 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. The CHPT is advised to file its proposal positively by 30 June 2016, as agreed by it.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./143/16(152)]